The Financial Express

15 May, 2017

Credit appetite in power, telecom, mining on the wane: Assocham

BANK CREDIT TO highly debt-ridden sectors like power, telecom and mining has been on a downhill, a trend that is likely to continue unless more steps are taken to weed out bad loans, industry body Assocham said on Sunday.

Analysing the RBI data, a paper prepared by the chamber noted that the mining sector, which has been battling slowdown in demand and pricing power, saw maximum de-growth in deployment of bank credit in 2016-17 by 11.5% at ₹345 billion in March 2017, from ₹390 billion in the same month of the previous year.

The government earlier this month empowered the RBI to ask banks to initiate insolvency proceedings to recover bad loans amounting to over ₹6 lakh crore in the case of state-owned lenders alone & promised more measures to resolve the NPA crisis. — PTI

The Free Press Journal (Mumbai) 15 May, 2017

Credit deployment to power and telecom sector declining: Assocham

• AGENCIES
New Delhi

An ASSOCHAM paper noted that with a declining appetite for both lenders and borrowers in debt-ridden sectors like power, telecom and mining, the deployment of bank credit to these has witnessed a plunge and the trend may continue unless the basic issue of red mark in the balance sheets of banks by way of Non-Performing Asset (NPAs) and the corporate firms in the form of back breaking leverage is addressed.

Analysing the data provided by the Reserve Bank of India (RBI), the paper noted that the mining sector, battling slowdown in demand and pricing power, saw a maximum of degrowth in deployment of bank credit in the financial year 2016-17, from Rs. 390 billion to Rs 345 billion in March, 2017.

Like mining and quarrying, including coal, the bank credit in the power sector saw a contraction of 9.4 per cent to Rs 5256 billion as of March, 2017

ASSOCHAM

from Rs 5799 billion a year ago.

The sector is battling issues like high debt level, low prices of merchandise power, unwillingness of the state-owned distribution firms to revise tariffs and a potential competition from solar energy, which, backed by government subsidy has seen the generators made bids for solar energy as low or even lower than the conventional sectors, reports ANI.

"Aggressive bidding for spectrum and intense competition for tariffs have brought the telecom sector as well to such a pass that the bank credit to the telcos is decreasing.

It has become a game of deep pockets but those pockets cannot be filled by borrowed money always," said D S Rawat, Secretary General- ASSOCHAM.

The bank credit to the telecom sector during 2016-17 dropped by 6.8 per cent to Rs 851 billion from 913 billion, adds the paper.

On the positive side, however, iron and steel sector recorded a 2.6 percent growth, from Rs 3155 billion to Rs 3195 billion. The paper attributed this growth to certain policy measures like restrictive imports from China.

Rashtriya Sahara

15 May, 2017

बिजली, दूरसंचार, खनन क्षेत्र में ऋण मांग घटी

■ नई दिल्ली।

भारी कर्ज के बोझ से दबे बिजली, दूरसंचार और खनन जैसे क्षेत्रों में बैंक ऋण में गिरावट आ रही है। उद्योग मंडल एसोचैम ने एक अध्ययन में कहा है कि यदि डूबे कर्ज से निपटने को और कदम नहीं उठाए गए, तो यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।

रिजर्व बैंक के आंकड़ों के विश्लेषण के बाद तैयार दस्तावेज में उद्योग मंडल ने कहा है कि खनन क्षेत्र में ऋण की मांग सबसे अधिक घटी है। बीते वित्त वर्ष 2016-17 में ऋण की वृद्धि दर 11 प्रतिशत घटकर मार्च, 2017 में 345 अरब रुपए पर आ गई, जो पिछले साल समान महीने में 390 अरब रुपए थी। सरकार ने इससे पहले इसी महीने रिजर्व बैंक को गैर निष्पादित आस्तियों के मामले में अधिक अधिकार दिए हैं। इसके तहत आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को डूबे ऋण के मामले में संबंधित कंपनी के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने को कह सकता है।

एसोचैम ने कहा है कि कोयला ब्लाक नीलामी को लेकर सारी चर्चा थम गई है। कोयले की कमजोर मांग और ताप बिजली घर को लेकर कमजोर परिदृश्य की कोयले की मांग नीचे आई है। तापबिजली घर पहले ही मूल्य और मांग के अनुमान के आधार पर क्षमता बढ़ाने की वजह से संघर्ष कर रहे हैं। बिजली क्षेत्र को भी ऋण मार्च, 2017 के अंत तक 9.4 प्रतिशत घटकर 5,256 अरब रुपए पर आ गया, जो एक साल पहले समान अवधि में 5,799 अरब रुपए था।

■ डूबे कर्ज से निपटने के लिए कदम उठाने की जरूरत

■ कर्ज की मांग में सबसे ज्यादा कमी खनन क्षेत्र में आई

दूरसंचार क्षेत्र भी अपवाद नहीं है। इस क्षेत्र को 2016-17 बैंक ऋण 6.8 प्रतिशत घटकर 851 अरब रुपए रह गया, जो एक साल पहले समान अवधि में 913 अरब रुपए था। एसोचैम के महासचिव डीएस रावत ने कहा, "स्पेक्ट्रम के लिए आक्रामक बोली तथा सेवाओं की दरों को लेकर कड़ी प्रतिस्पर्धा से दूरसंचार क्षेत्र ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जिसमें दूरसंचार कंपनियों के लिए बैंकों का ऋण घट रहा है। यह गहरी जेब का खेल बन गया है, लेकिन इस जब को हमेशा कर्ज के पैसे से भरा नहीं रखा जा सकता।'

हालांकि, लौह एवं इस्पात क्षेत्र में ऋण की वृद्धि सकारात्मक रहीं इस क्षेत्र में ऋण 2.6 प्रतिशत बढ़कर 3,195 अरब रुपए पर पहुंच गया, जो एक साल पहले समान अवधि में 3,155 अरब रुपए था। ■ भाषा

Navodaya Times

15 May, 2017

बिजली, दूरसंचार, खनन क्षेत्र में ऋण मांग घटी

नई दिल्ली, 14 मई (एजेंसी): द्योग मंडल एसोचैम ने एक अध्ययन में कहा है कि यदि डूबे कर्ज से निपटने को और कदम नहीं उठाए गए तो ऋण मांग में गिरावट का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।

उद्योग मंडल ने कहा है कि बीते वित्त वर्ष 2016-17 में ऋण की वृद्धि दर 11 प्रतिशत घटकर मार्च, 2017 में 345 अरब रुपए पर आ गई बिजली क्षेत्र का भी ऋण मार्च, 2017 के अंत तक 9.4 प्रतिशत घटकर 5256 अरब रुपए पर आ गया।

दूरसंचार क्षेत्र भी अपवाद नहीं है। इस क्षेत्र का 2016-17 बैंक ऋण 6.8 प्रतिशत घटकर 851 अरब रुपए रह गया, जो एक साल पहले समान अवधि में 913 अरब रुपए था।